Indira Awas Yojana

766. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINSTER be pleased state:

(a) the year of the introduction of Idira Awas Yojana;

(b) the target set for the construction of houses under the scheme by the end of the 8th Five Year Plan;

(c) the State-wise targets achieved so far; and

(d) the expenditure incurred on the construction of houses under Indira Awas Yojana so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURALS AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The Scheme of Indira Awas Yojana (IAY) was introduced in 1985-86 in the central sector to provide houses free of cost to SCs/ST sand freed bonded labourers. Upto 1992-93, 6 per cent of Jawahar Rozgar Yojaan (JRY) allocation at national level used to be earmarked for IAY and central assistance was provided to rural poor belonging to SCs/STs for construction of their own houses from 1993-94 onwards, the earmarking under LAY has been increased from 6 per cent to 10 per cent of the JRY allocations and coverage has been extended to non-SC/ST rural poor subject to the conditions that the financial benefit to non-SC/ST people does not extend of the JRY allocation.

(b) The target under IAY is fixed on the basis of annual allocations. The target, therefore, is fixed annually and not plan-wise. The target fixed for 1992-93 to 1994-95 are as under:—

1992-93	—	117133 (no.)
1993-94	—	280363
1994-95	—	353353

(c) and (d) Since inception of Indira Awas Yojana, a number of 18,92,206 houses have been constructed and an amount of Rs. 2263.81 crores has been spent so far. The State-wise targets and achievements and the expenditure incurred on the construction of houses under IAY so far is given in the enclosed annexures (*See* **Appendix 173, Annexure No. 24**).

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में सर्वेक्षण

767. श्री ईश दत्त यादव :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में 1991 में कोई सर्वेक्षण करवाया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष थे ; और

(ग) उन निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) **(श्री उत्तमभाई पटेल)** : (क) राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक योजना अवधि के शुरु में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए सर्वेक्षण कराना होता है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसा सर्वेक्षण नवम्बर, 1991 में शुरु किया गया था ।

(ख) और (ग) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि काफी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । सरकार ने प्रति परिवार निवेश के स्तर में वृद्धि करके, बहु-परिसम्पत्तियां मुहैया कराने हेतु

परिवार ऋण योजना का विस्तार करके कार्यक्रम हेतु आधारभूत ढांचा सहायता को मजबूत बनाने आदि जैसे उपायों की मार्फत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करके गरीबी में कमी लाने के प्रयासों में वृद्धि की है ।

कापार्ट द्वारा रोजगार पैदा करने हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन

768. **श्री आस मोम्हमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" ने ग्रामीण जनता के लिए रोजगार पैदा करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "कापार्ट" द्वारा पैदा किए गए रोजगार के अवसरों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने ग्रामीण लोगों को इनसे लाभ हुआ है ;

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान इससे कितने लोगों को लाभ होने की संभावना है;

(च) उक्त योजना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(छ) शेष धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) कापार्ट स्वैच्छिक एजेन्सियों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना है ।

(ग) व (घ) कापार्ट द्वारा कार्यान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना की परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 77.74 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया है ।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(च) व (छ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कापार्ट को निधियां स्वयं सेवी एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष रिलीज की जाती है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कापार्ट को पिछले तीन वर्षों के दौरान 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कापार्ट ने इस अवधि के दौरान उपलब्ध आदि शेष सहित 26.53 करोड रुपये का उपयोग किया गया है ।

मध्य प्रदेश के शहरों के लिए जल आपूर्ति योजना

769. **श्री राघवजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 लोगों से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो वे शहर कौन-कौन से हैं, जिनके लिए योजनाएं भेजी गई हैं। क्या इनकी लागत कितनी-कितनी है और कौन-कौन सी तिथियों को ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई थीं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या-क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।